Publication	**Rajasthan Patrika**	**Language**	Hindi
Edition	New Delhi	**Journalist**	The Edit Desk
Date	25/02/2025	**Page no**	6
CCM	78.57		

India set an example by strengthening the cooperative movement

बदलाव : 48 हजार पैक्स ने किसी न किसी नई गतिविधि को अपने साथ जोड़कर 'वायबल' बनने की दिशा में पहल की है

सहकारिता आंदोलन को मजबूत कर मिसाल बना भारत

मोहित टांटिया
भारतीय खाद्य निगम की परामर्श समिति के सदस्य
@patrika.com

आजादी के बाद सहकारिता आंदोलन किसी न किसी तरह आगे बढ़ता रहा। सरकार ने 2021 में 'सहकार से समृद्धि' का नारा देते हुए इस क्षेत्र के लिए स्वतंत्र मंत्रालय भी बना दिया।

संयुक्त राष्ट्र यह साल अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में मना रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने इसे 'बेहतर विश्व का निर्माण करती सहकारिता' की थीम के साथ मनाने का फैसला किया है। यह थीम दुनिया भर में सहकारिता के स्थायी प्रभाव पर प्रकाश डालती है और इस बात पर जोर देती है कि सहकारी मॉडल अनेक तरह की वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए महत्त्वपूर्ण समाधान हैं। दुनिया भर में सहकारिता व सहकारिता आंदोलन की चर्चा भारत के योगदान के बिना पूरी नहीं हो सकती, यह तय बात है।

भारत ने सहकारिता आंदोलन को जिस तरह से मजबूत किया है, वह अपने आप में मिसाल है। इस आंदोलन ने देश के लाखों लोगों का जीवन बदलने में बड़ी भूमिका निभाई है और निभा रहा है। सबसे बड़ी बात कि सरकार अब 'सहकार से समृद्धि' की थीम के साथ इस आंदोलन को मजबूत कर रही है। देश में सहकारिता आंदोलन की मौजूदा स्थिति व भविष्य की चर्चा से पहले हमें इसके इतिहास पर एक नजर डालनी होगी। भारत में औपचारिक सहकारिता को सवा सौ साल के करीब हो चुके हैं। हालांकि हमारे यहां अवधारणा उससे भी कहीं पहले से चली आ रही है। भले ही इसके रूप अलग रहे हों। ग्रामीणों द्वारा सामूहिक इस्तेमाल के लिए जोहड़ों-कुंओं का निर्माण व प्रबंधन हो या पशुधन के लिए ओरण व गोचर भूमि या गांव के जंगल देवराई व वनराई का प्रबंधन। यह एक तरह की सहकारिता ही थी। खैर, 1904 में इस दिशा में पहला अधिनियम कॉआपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी आया और इसके बाद औपचारिक सिलसिला चल पड़ा।

देश में सहकारिता आंदोलन में एक बड़ी घटना 1946 में हुई जब सरदार वल्लभ भाई पटेल से प्रेरित होकर मोरारजी देसाई व त्रिभुवनदास पटेल के नेतृत्व में गुजरात के खेड़ा जिले के दुग्ध उत्पादकों ने हड़ताल की। उन्होंने दूध की आपूर्ति बंद कर दी तो तत्कालीन बॉम्बे सरकार अपना वह आदेश वापस लेने को मजबूर हुई, जिसमें एक प्राइवेट डेयरी पॉलसन को एकाधिकार अधिप्राप्ति अधिकार दिए गए थे। इसके बाद दो प्राथमिक ग्राम दुग्ध उत्पादक समितियां अक्टूबर 1946 में पंजीकृत हुईं तो इसके तुरंत बाद चार दिसंबर, 1946 को खेड़ा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक मिल्क यूनियन पंजीकृत की गई, जिसे अमूल के नाम से जाना गया। आजादी के बाद सहकारिता आंदोलन किसी न किसी तरह आगे बढ़ता रहा। केंद्र सरकार ने जुलाई 2021 में 'सहकार से समृद्धि' का नारा देते हुए इस क्षेत्र के लिए स्वतंत्र मंत्रालय बनाने की दशकों पुरानी मांग को पूरा किया। इस मंत्रालय का उद्देश्य सहकारी समितियों को एक सच्चे जन-आधारित आंदोलन के रूप में जमीनी स्तर तक पहुंचाना और सहकार आधारित आर्थिक मॉडल विकसित करना है, जहां प्रत्येक सदस्य जिम्मेदारी की भावना के साथ काम करता है। मंत्रालय हर गांव को सहकारिता से जोड़ने, हर गांव को सहकार से समृद्धि के मंत्र से समृद्ध बनाने पर जोर देता है।

सहकारिता मंत्रालय के अब तक कई महत्त्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सरकार ने लक्ष्य रखा है कि कि देश में कोई राज्य या जिला ऐसा ना हो जहां एक 'व्यावहारिक' (वायबल) जिला सहकारी बैंक और जिला दुग्ध उत्पादक संघ न हो। इसका उद्देश्य न केवल सहकारिता का दायरा बढ़ाना, बल्कि हर ग्रामीण और गरीब को समृद्ध बनाना है। इसके लिए सहकारिता युक्त पंचायत की कल्पना की गई है। दरअसल, आज भी देश में लगभग दो लाख पंचायतों में कोऑपरेटिव संस्था नहीं है। मंत्रालय ने लक्ष्य रखा है कि अगले पांच साल में इन पंचायतों में मल्टीपर्पज पैक्स गठित की जाएं। केंद्र सरकार ने पैक्स के 'मॉडल बायलॉज' भी बनाए हैं और पैक्स राज्य का विषय होने के बावजूद राज्यों ने इन मॉडल बायलॉज को स्वीकार किया है। सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2029 तक देश में एक भी पंचायत ऐसी न हो, जहां पैक्स न हो। सबसे बड़ी बात आज देश में कार्यरत 65000 में से 48000 पैक्स ने किसी न किसी नई गतिविधि को अपने साथ जोड़कर 'वायबल' बनने की दिशा में पहल की है। देश का सहकारिता आंदोलन आज कई क्षेत्रों में अपना बड़ा योगदान दे रहा है। इसका कृषि ऋण के वितरण में 20 प्रतिशत, उर्वरकों के वितरण में 35 और उत्पादन में 21 प्रतिशत, चीनी उत्पादन में 31 प्रतिशत, गेहूं खरीद में 13 प्रतिशत और धान की खरीद में 20 प्रतिशत का योगदान है। ग्रामीण और कृषि अर्थव्यवस्था में इस क्षेत्र का अपना एक महत्त्व है, जिसकी अनदेखी नहीं की जा सकती।

दरअसल सहकारिता ही वह रास्ता है, जिसके जरिए आम लोग बिना पूंजी के न केवल खुद का विकास कर सकते हैं बल्कि देश के विकास में योगदान दे सकते हैं। सहकारिता को देश के अर्थ तंत्र का एक मजबूत स्तंभ बनाकर करोड़ों गरीबों के जीवन में सुविधाएं व समृद्धि ला सकते हैं, उनके आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं। गैर सरकारी संगठनों व आम जनता को भी इसमें सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए।

****

Downloaded from
SAMVAD